



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

No. 212]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2004/भाद्र 23, 1926

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2004/BHADRA 23, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

जांच शुरुआत

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय: ई यू, जापान और यूएसए के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित हाइड्रॉक्सीलेमीन सल्फेट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत

सं. 15/23/2004-डीजीएडी:- यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियम कहा गया है) के अंतर्गत दिनांक 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 53/1/99-डीजीएडी के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, यूएसए और जापान (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित हाइड्रॉक्सीलेमीन सल्फेट (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था।

और यतः दिनांक 28 मार्च, 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 31/2001-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यतः उपरोक्त नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी प्राप्त निश्चयात्मक सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इस प्रकार के शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं। उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गयी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करने वाली निश्चयात्मक सूचना के आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक उचित

समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटन के प्रतिसंतुलन के लिए शुल्क को लगातार जारी रखना आवश्यक है, कि शुल्क की समाप्ति अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाएं तो क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यूरोपीय संघ के एक निर्यातक अर्थात् मै0 बी ए एस एफ लिमिटेड, जर्मनी ने लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा के लिए यूरोपीय आयोग के जरिए अनुरोध किया है।

समीक्षा के लिए आधार

4. आवेदक ने दावा किया है कि पाटन और क्षति दोनों की परिस्थितियाँ काफी परिवर्तित हो गई हैं जिनके कारण लागू पाटनरोधी उपायों की समीक्षा करना आवश्यक है। निर्यातक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से मै0 बी ए एस एफ द्वारा भारत को अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत निर्यातों के अतिरिक्त अंतिम प्रयोग के लिए कोई सीधा निर्यात नहीं किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि पाटनरोधी उपायों से एच ए एस की घरेलू खपत में याचिकाकर्ता के हिस्से में कोई सुधार नहीं हुआ है।

5. इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि बेलारूस से कम कीमत पर निर्यातों के कारण एच ए एस के घरेलू प्रयोक्ताओं ने दीपक नाइट्राइट (घरेलू उद्योग) से एच ए एस नहीं खरीदा है। आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आवेदक ने दावा किया है कि एच ए एस, जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रतिजैविकों के उत्पादन में होता है जिनका प्रयोग प्रतिजैविक एस एम एक्स/एस एम जेड के उत्पादन में होता है, की घरेलू मांग में कमी होने के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। यह भी दावा किया गया है कि प्रतिजैविकों के लिए विश्व बाजार में चीनी निर्यातकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा कीमत में कमी के कारण कई भारतीय कंपनियों ने एस एम एक्स/एस एम जेड के बाजार को छोड़ दिया है। मै0 दीपक नाइट्राइट लि0 के दो वर्तमान प्रभागों (सोडियम नाइट्राइट तथा सोडियम नाइट्रो-एरोमेटिक्स) के समेकन से लागतों में कटौती करके दक्षता में वृद्धि होगी। आवेदक ने दावा किया कि इस पुनर्संरचना से एच ए एस के उत्पादन तथा लागत पर प्रभाव पड़ेगा। अतः आवेदक का दावा है कि यूरोपीय संघ से कोई पाटन नहीं हो रहा है और घरेलू उद्योग को यूरोपीय संघ से होने वाले आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

जांच शुरूआत

6. परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई निश्चयात्मक सूचना के मद्देनजर लागू उपाय की समीक्षा करना जरूरी हो जाने के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम

1995 की धारा 9क (5) के प्रावधान के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित समझते हैं।

7. दिनांक 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं० 53/1/99-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा का निर्णय लेकर प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमों के अनुसार जांच आरम्भ करते हैं ताकि यह समीक्षा की जा सके कि क्या यूरोपीय संघ, यूएसए और जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एच ए एस के आयातों पर शुल्क को लगातार लगाया जाना पाटन के प्रति संतुलन के लिए जरूरी है, शुल्क को समाप्त अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाने से क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

विचाराधीन उत्पाद

8. मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद हाइड्रॉक्सीलेमीन सल्फेट है जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सीमाशुल्क उपशीर्ष के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

प्रक्रिया

9. जांच द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पाटन की समाप्ति के लिए शुल्क को जारी रखा जाना आवश्यक है तथा क्या शुल्क के हटाए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों से क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) समीक्षा में दिनांक 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं० 53/1/99-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

(ii) इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 की है। तथापि क्षति विश्लेषण की अवधि, वर्ष 2000-01 से वर्ष 2003-04 तक की होगी।

(iii) इस जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, यूएसए तथा जापान हैं।

सूचना देना

10. संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में एवं तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करें एवं अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराएं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

11. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपने निवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन करने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसे जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा।

समय-सीमा

12. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु किसी प्रकार के अनुरोध लिखित में भेजे जाने चाहिए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

13. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2004

Initiation**(Mid-term Review)**

Subject: Initiation of Mid-term Review of anti-dumping duty imposed on imports of Hydroxyl Amine Sulphate (HAS) originating in or exported from the EU, USA, and Japan.

No. 15/23/2004-DGAD.- WHEREAS having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), vide Notification Number 53/1/99-DGAD dated 1st March, 2001 the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Hydroxylamine Sulphate (HAS) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from European Union European Union, USA and Japan (hereinafter referred to as subject countries).

AND WHEREAS definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 31/2001-Customs dated 28th March, 2001.

Request for Review

2. WHEREAS the Rules require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of positive information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive antidumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

3. In terms of the above provision one of the exporters from the European Union i.e. M/s BASF Limited, Germany has filed a request, through the European Commission, for a changed circumstances mid-term review of the antidumping duty in force.

Grounds for Review

4. The applicant claims that the conditions of both, dumping and injury have changed substantially requiring a review of the antidumping measure in force. The exporter has *inter alia* claimed that there are no direct exports for end use except against Advance License Scheme by M/s BASF to India since the imposition of the anti-dumping duty. It has also been claimed that the AD measures have not led to any improvement in the share of the petitioner in the domestic consumption of HAS.

5. It is further stated that the domestic users of HAS have not purchased HAS from Deepak Nitrite (Domestic Industry) due to low priced exports from Belarus. It has been claimed by the applicant that despite the imposition of AD Duty, the position of Domestic Industry has not improved. The applicant has claimed that the circumstances have changed due to decrease in domestic demand for HAS which is mainly used in the production of antibiotic, used in the production of antibiotic SMX/SMZ. It is also claimed that a number of Indian companies have abandoned the SMX/SMZ market due to intense competition from Chinese exporters in the World Market for antibiotics and reduction in price. The consolidation of two of its existing divisions (Sodium Nitrite and sodium Nitro-aromatics) of M/s Deepak Nitrite Ltd. will increase its efficiency by cutting costs. The applicant has claimed that this restructuring will affect production and cost of HAS. Therefore, the applicant claims that no dumping is taking place from the European Union and the domestic industry is not suffering any injury on account of the imports from the European Union.

Initiation

6. Having regard to the information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the Anti Dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra.

7. Having decided to review the final findings notified vide Notification No. 53/1/99-DGAD dated 1st March, 2001, the Authority hereby initiates the investigations in terms of the Rules, to review whether continued imposition of the duty on imports of HAS originating in or exported from the USA, Japan and European Union is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

Product under Consideration

8. The product involved in the original investigation and the current review is Hydroxylamine Sulphate(HAS) falling under Chapter 28 of the Customs sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Procedure

9. The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping if any, whether the injury is likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No.53/1/99-DGAD dated 1ST March,2001.
- (ii) The period of investigation for the purpose of this review will be 1st April 2003 to 31st March 2004. However, injury analysis shall cover the years from 2000-01 to 2003-04.
- (iii) The countries involved in this investigation are the European Union,USA and Japan.

Submission of Information:

10. The exporters in subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.
Fax: 91-11-23014418

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making confidential submissions before the Authority is required to file a non-confidential version of the same, for placing the same in the public folder for inspection by all other interested parties to the investigation.

Time Limit

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned

above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

Inspection of Public File:

12. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the submissions made by other interested parties before the Authority. In case an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority